

मेरा नजरिया यह है कि अगर आपको
इंद्रधनुष चाहिए तो बरसात की बौछार सहन
करनी होगी। डॉली पॉर्टन

क्रांतिकारी कढम

मुस्लिम महिलाओं की आजादी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए एक साथ तीन तलाक की बुरी, अमानवीय और अदिमकालीन प्रथा को आपराधिक घोषित करने वाला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2017 लोक सभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक प्रावधान करता है कि इस्लाम का कोई भी अनुयायी अपनी पती को एक बार में तीन तलाक किसी भी माध्यम (ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस) से देगा तो उसे तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते अगस्त में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ सदियों से चली आ रही उस अमानवीय और कूर प्रथा को असंवैधानिक ठहराते हुए सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का आदेश दिया था। क्या यह अपने आप में विरोधाभासी नहीं है कि इस तरह के प्रगतिशील कदम की अपेक्षा कांग्रेस-वामपर्वथियों जैसी पार्टियों से थी? लेकिन दक्षिणपंथी और यथास्थितिवादी समझी जाने वाली भाजपा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षक बनकर सामने आई। हालांकि इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। सचाई तो यह है कि सामाजिक बुराइयों का अंत भी आखिर इसी जरिए से होता रहा है। अचरज इस बात पर है कि विधेयक का सर्वाधिक विरोध उन दलों ने किया जो सामाजिक न्याय के पैरोकार होने का दावा करते हैं। इस क्रम में लोक सभा में राजद और बीजद का विरोध और टीएमसी की चुप्पी के पीछे सिवाय वोटों की राजनीति के दूसरी दृष्टि नहीं है। दरअसल, कट्टपंथी, रुद्धिवादी और यथास्थितिवादियों की राजनीतिक दुकान किसी भी प्रगतिशील कदम के विरोधपर ही चलती है। इनके सिवाय सभी ने विधेयक का समर्थन किया है। सच तो यह है कि यह विधेयक जिनके हक में है, जब उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है, तो वाकी लोगों के विरोधका कोई मतलब नहीं रह जाता। कांग्रेस समेत कुछ अन्य राजनीतिक दलों की आपत्ति विधेयक के सजा वाले प्रावधान से संबंधित है। सजा का प्रावधान निरोधक का काम करेगा, फिर भी सजा की मियाद और इस कानून को लागू करने की राह में आने वाली अड़चनों पर सरकार को विचार करना चाहिए। बहरहाल, सरकार के इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम का स्वागत करना चाहिए। इसे हिन्दू-मुसलमान वोट की सियासत से देखने के बजाय सिर्फ महिला अधिकार की दृष्टि से देखने की जरूरत है।

बैंकिंग बदल रही है

आज दरें बदल रही हैं। बैंकिंग बदल रही है। आम आदमी की समझ में सब कुछ नहीं आ रहा है। नासमझी या कम समझी के चलते उसकी जेब पर चपत लग रही है। अभी ही लघु बचत की ब्याज दरों में दशमलव 20 की कमी की गयी यानी पब्लिक प्रॉवीडेंट फंड पर जो ब्याज सालाना 7.8 प्रतिशत था, अब घटकर 7.6 प्रतिशत रह जायेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज 7.5 प्रतिशत था, यह घटकर सालाना 7.3 प्रतिशत रह जायेगा। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर जो ब्याज दर 7.8 प्रतिशत थी, वह घटकर 7.6 प्रतिशत हो जायेगा। यानी आम आदमी ब्याज से कम कमा पायेगा। पर आफतें सिर्फ़इतनी नहीं हैं। बैंक उपभोक्ताओं से तरह-तरह से वसूली करते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के मुताबिक 2017-18 के दौरान करीब 2000 करोड़ रु पये दंड के वसूले जायेंगे इस बैंक के उन ग्राहकों से, जिनके खातों में बैलेंस न्यूनतम बैलेंस से नीचे चला जाता है। ब्याज दरों के लगातार कम होने के ही आसार हैं, क्योंकि ब्याज दरों का ताल्लुक होता है महंगाई से। महंगाई की दर अगर लगातार बढ़ती है तो ब्याज दरों का बढ़ाना बनता है। इसका सामान्य-सा अर्थशास्त्र यह है कि आगर किसी ने किसी को सौ रुपये उधार दिये हैं। दिसम्बर 2017 में और उसकी वापसी अगले साल यानी दिसम्बर 2018 में होनी है, तो जाहिर है दिसम्बर 2018 में सौ रुपये की बैल्यू वह न रह जायेगी जो दिसम्बर 2017 में थी। यानी दिसम्बर 2017 में जो चीजें 100 रु पये की आयेंगी, एक साल बाद वे ही चीजें खरीदने के लिए 105 रु पये या ज्यादा चाहिए होंगे, ये पांच रु पये जो बढ़ते हैं, यह महंगाई दर होती है। तो सौ रु पये लेकर अगर कोई 105 वापस दे रहा है, तो महंगाई दर के चलते कुछ वापस हो नहीं पा रहा है। यानी अगर ब्याज दर सात प्रतिशत हो आठ प्रतिशत तब जाकर कुछ रिटर्न मिलेगा। नवम्बर 2017 में उपभोक्ता महंगाई सूचकांक 4.88 प्रतिशत रही है, ऐसी सूरत में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की ब्याज दर 7.6 प्रतिशत है। अगर महंगाई दर और गिरी तो ब्याज दर और गिरेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध दिखायी देता है, ऐसी सूरत में वह पुराना दौर लौटकर न आयेगा, जिसमें महंगाई दर 12 प्रतिशत होती थी और ब्याज दर 19 प्रतिशत तक जाती थी। अब जरूरी है निवेशक रिटर्न के दूसरे रास्तों को देखें। मुचुअल फंड वगैरह में निवेश को देखें यो दीर्घावधि में औसत रिटर्न 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत सालाना तक रहता है।

सत्यंगा

ੴ

भय को न मारा जा सकता है, न जीता जा सकता है, केवल समझा जा सकता है और केवल समझ ही रूपांतरण लाती है, बाकी कुछ नहीं। अगर तुम अपने भय को जीतने की कोशिश करोगे, तो यह दबा रहेगा, तुम्हारे भीतर गहरे में चला जाएगा। उससे कुछ सुलझेगा नहीं बल्कि चीजें और उलझ जाएंगी। जब भय उठे तो तुम उसे दबा सकते हो— भय को जीतने का यही अर्थ है। भय को तुम मार नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है और कोई भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। तुमने कभी देखा भय के समय तुम्हारे एकदम से बड़ी ऊर्जा आ जाती है? ठीक जैसे क्रोध के समय ऊर्जा आ जाती है; वे दोनों एक ही ऊर्जा के दो आयाम हैं। क्रोध आक्रामक है और भय अनाक्रामक है। भय है क्रोध की गिरेटिव अवस्था और क्रोध है भय की पॉजिटिव अवस्था। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारे कितनी ताकत आ जाती है, ऊर्जा भर जाती है! जब तुम क्रोध में होते हो तो एक बड़ी चट्टान भी उठाकर फेंक सकते हो; आम तौर पर उतनी बड़ी चट्टान तो तुम हिला भी नहीं सकते। क्रोध के समय तुम तीन-चार गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हो। उस समय तुम ऐसी कई चीजें कर सकते हो, जो क्रोध के बिना संभव ही नहीं हैं। और भय के समय तुम इतना तेज भाग सकते हो कि ओलंपिक खिलाड़ी भी ईर्ष्या करने लगे। भय से ऊर्जा पैदा होती है; भय ऊर्जा ही है, और ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अस्तित्व से ऊर्जा की एक चुटकी भी नष्ट नहीं की जा सकती। इस बात को हमेशा याद रखो, वरना तुम कुछ गलत कर बैठोगे। तुम किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसका रूप बदल सकते हो। छोटे से कंकड़ को भी तुम नष्ट नहीं कर सकते। रेत का एक छोटा-सा कण भी नष्ट नहीं किया जा सकता। वह केवल अपना रूप बदल लेगा। पानी की एक बूंद को भी तुम नष्ट नहीं कर सकते। वह रहेगी, इस अस्तित्व से बाहर तो जा नहीं सकती। लोग भय को नष्ट करने की, क्रोध को, काम को, लोभ को और ऐसी कितनी ही चीजों को नष्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। पूरी दुनिया इसी तरह कोशिश करती रही है, और परिणाम क्या हुआ? मनुष्य उथल-पुथल हो गया है। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वसा है, बस चीजें उलझ गई हैं। कुछ भी नष्ट करने की जरूरत नहीं है।

विवाह में अधिकारों की रक्षा

देश में मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक मामलों में क़ानूनी संरक्षण की दिशा में यह अति महत्वपूर्ण कदम है। वैसे मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक मामलों और विशेषकर ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर राजनीति और पितृसत्ता का खूब खेल खेला गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खुद मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुहीम छेड़ कर इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका द्वारा साधारण महिलाओं ने बड़ी-बड़ी धार्मिक, पितृसत्तात्मक एवं राजनैतिक ताकतों को चुनौती दी है।

सतीश पेटणोकर

इस विधेयक को सार्विधानिक जेंडर जस्टिस और लोकतांत्रिक नज़रिये से देखा जाना चाहिए। विधेयक का मकसद लैंगिक न्याय के साथ युनहगार को सजा दिलाना भी है। कानून का अमल सही तरीके से होने से एवं सजा के डर से ही अपराध कम हो सकता है। अब क्या इस कानून को महज इसलिए ढुकरा दिया जाए कि यह बीजेपी सरकार की पहल का नतीजा है। तब तो यह मुस्लिम महिलाओं के साथ सरासर ज्यादती होगी और लोकतंत्र का मजाक बनाना होगा मुस्लिम महिला (विवाह में अधिकारों की रक्षा) विधेयक-2017 कल लोक सभा से पारित हो गया। भारतीय लोकतंत्र का यह एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पदङ्गत है। देश में मुस्लिम महिलाओं को परिवारिक मामलों में कानूनी संशोधन नई विधा से एवं अधिकारों के बढ़ावा दिया जाएगा।

संरक्षण की दिशा में यह अति महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक मामलों और विशेषकर ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर राजनीति और पितृसत्ता का खूब खेल खेला गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खुद मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुहीम छेड़ कर इस खेल का पदार्थकाश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका द्वारा साधारण महिलाओं ने बड़ी-बड़ी धार्मिक, पितृसत्तात्मक एवं राजनीतिक ताकतों को चुनौती दी है। हैरानी की बात है कि शादी और परिवार से जुड़े मामलों में हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ कानूनी भेदभाव होते आए हैं। और यह आजादी के 70 सालों के बाद भी जारी है। देश का संविधान पारिवारिक मामलों में हर नागरिक को मजहब आधारित कानून के अनुसरण की इजाजत देता है। इसी के चलते देश में हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955; हिन्दू सक्षेपशन एक्ट, 1956 और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जिसमें 2000 में संशोधन हुआ जैसे कानून लागू हैं। इन सभी कानूनों में संसद ने लगातार सुधार किये हैं ताकि जेंडर जस्टिस का मकसद हासिल हो सके। दूसरी ओर, देश के मुसलमान समाज में शरीअत एस्टीकेशन एक्ट, 1937 यानी की अंग्रेज सरकार के ज़माने का कानून लागू है और इसमें आज तक कोई सुधार या संशोधन नहीं हुआ है। इसी वजह से ट्रिपल तलाक, निकाह हलाता एवं बहुपतीत्व जैसी स्त्री विरोधी प्रथाएं चलती आई हैं। इंसाफ के कुरानी आयामों और सांविधानिक उस्लूमों के बावजूद मुस्लिम महिला के साथ खुलेआम नाइंसाफी होती आई है। पुरुष घवाड़ी मानसिकता के धार्मिक संगठनों के वरचय के चलते मुस्लिम महिलाओं को उनके हक्कों से वंचित रखा गया है। ये ऐसी पितृसत्तात्मक साजिश है, जिसमें धार्मिक संगठनों के अलावा राजनीतिक वर्ग भी पूरी तरह से शामिल रहा है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी दोषी नहीं है। मौजूदा विधेयक को इस रोशनी में समझने को जरूरत है। ट्रिपल तलाक को याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। लेकिन इससे पहले लम्बे अरसे से मुस्लिम महिलाएं कानून की गुहार लगाती आई हैं। हमने लगातार कहा है कि कानून हमारी जरूरत ही नहीं, बल्कि हमारा मन्त्रैधार्णिक अधिकार भी है। टिम्बल्बूर 2012 में मंबैर्ड में मालिनम

महिलाओं के राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने ट्रिपल तलाक के खात्मे का आह्वान किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत भी लिखा था। इसमें मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाया जरूरी बताया था। तत्कालीन उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मुलाकात एवं बैठक भी की थी। उसके बाद से लेकर मुस्लिम महिलाएं इंसाफ के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, देश में ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक आम राय बन चुकी थी। शायरा बानो अब 1986 की शाह बानो की तरह अकली नहीं थी, उसे न केवल देश की मुस्लिम महिलाएं बल्कि समूची महिला आवादी का साथ मिला था। यह कहना अतियुक्त नहीं होगा कि इसी महिला समन्वय के चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला संभव हो सका वरना सार्विधानिक प्रावधान तो हमेशा से मौजूद थे। विधेयक लाने के लिए केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की कोशिश सराहनीय है। साथ ही, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्ष द्वारा कानून का समर्थन दिया

का उल्लंघन करता है तो उसे सजा ज़खर मिले। लेकिन उसका जुर्म है और केस दर्ज कराने का हक पती का हो। वे चाहें तो केस दर्ज करवाएँ और कोर्ट पति को जेल या अन्य सजा दें; चाहे तो इसे गैर-जमानत जुर्म बनाया जाए। इस सुधार से कानून के दुरुपयोग की आशंका नहीं रहेगी। विधेयक का मक्सद जेंडर जस्टिस है और गुनहगार को सजा दिलाना भी। कानून का अमल सही होने से एवं सजा के डर से ही अपराध कम हो सकता है। अब क्या इस कानून को महज इसलिए तुकरा दिया जाए कि यह बीजेपी सरकार की पहल का नतीजा है। यह तो मुस्लिम महिलाओं के साथ सरासर ज्यादती होगी और लोकतंत्र का मजाक बनाना होगा।

चलते चलते

अलविदा-2017

अलविदा ! अलविदा, गौरी लंकेश को हमेशा के लिए सुलाने वाले साल। अलविदा, दाभोलकर, पानसरे तथा कलबुर्गी की तरह, उनके मामले में भी पुलिस को कोई लीड न मिल पाने के साल। ट्रोल सेना के गांधी की हत्या की तरह, इस हत्या पर भी खुशियां मनाने के और पीएम जी के एक बार फिर एकदम चुप्प लगा जाने के साल, अलविदा। केसरिया राज में राजपूताने में गोरक्षकों से लेकर, स्वच्छता-रक्षकों तक के हाथों आबादी घटवाने वाले साल; पद्मावती से लेकर हल्दीघाटी की लड़ाई तक, सारा इतिहास सुधरवाने वाले साल; बाबू लाल रैगर को नया गोडसे बनाकर पुजवाने और उदयपुर में अदालत पर तिरंगे की जगह केसरिया फहराने को राष्ट्रभक्ति बनाने वाले साल; तमाम गैर-केसरिया पञ्जिक को और

अलविदा, दाभोलकर, पानसरे तथा
कलबुग्गी की तरह, उनके मामले में भी
पुलिस को कोई लीड न मिल पाने के
साल। ट्रोल सेना के गांधी की हत्या की
तरह, इस हत्या पर भी खुशियां मनाने वाले
और पीएम जी के एक बार फिर एकदम
चुप्प लगा जाने के साल, अलविदा।
केसरिया राज में राजपूताने में गोरक्षकों

लेकर, स्वच्छता-रक्षकों तक के हाथों
आवादी प्रवाहों वाले माल

विकास-फिकास सब भुलवा देने और नानी नाना के अलावा पाकिस्तान याद कराने वाले साल; शाह को जीतकर भी हार की-सी पीलिंग दे जाने वाले साल, अलविदा। आडवार्ण जी, जोशी जी से रिटायरमेंट का एक औंस साल कटवाने वाले, पर यशवंत को रिबेल बनवाने वाले साल, अलविदा। नोटवंदी की चोट पर, जीएसटी की चोट मारने वाले; किसानों को बागी बनाने वाले; रोजगार को जुम्ला बनाने वाले; नीतीश को केसरिया भक्त में पलटवाने वाले; एक मंत्री से संविधान को पलटने के एलान कराने वाले; राम सेतु पर अमरीकी मोहर लगावाने वाले; इकॉनामी का भद्दा बैठाने वाले महंगाई का जोर दिखाने वाले; शाह-जादे वे हल्ले में युवराज को मजे में तख्तनशीन कराने वाले साल, तू जा ताकि 2018 आए। जो तुझसे नहीं बना शायद वही कर पाए। हँसी न सही

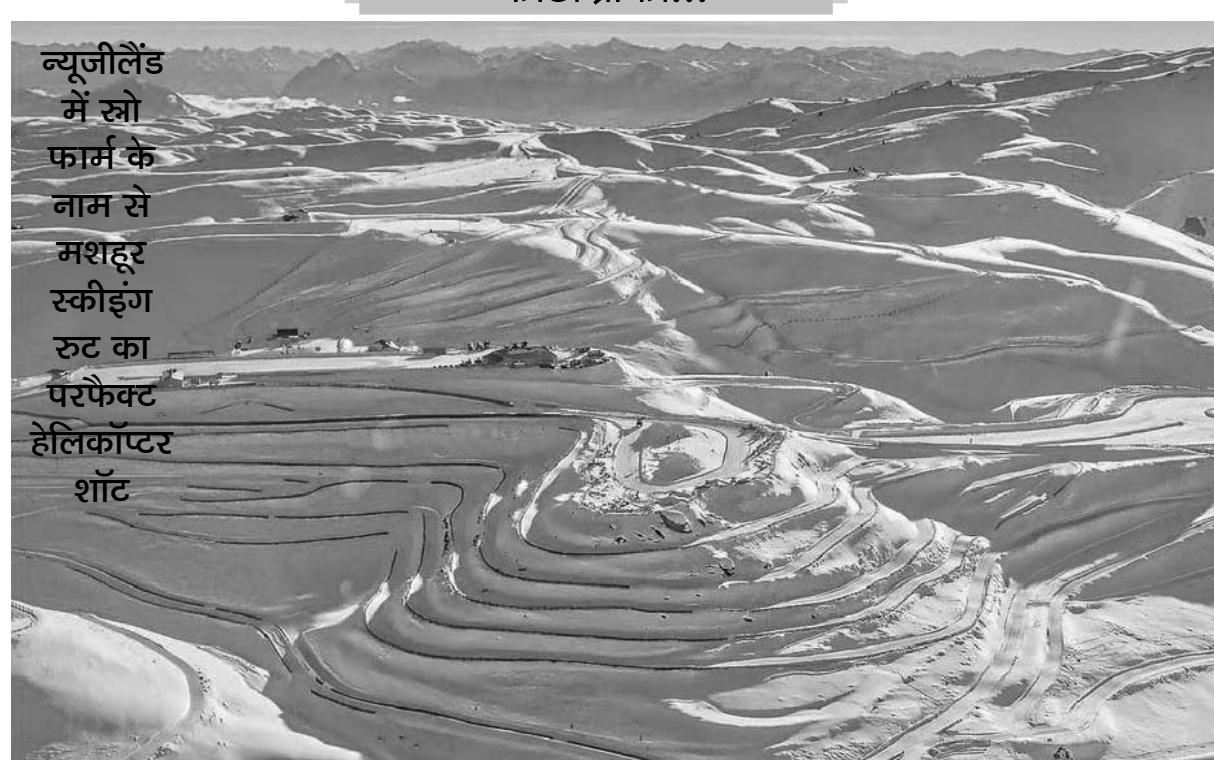
पब्लिक के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट तो लाए

‘सुविधा शुल्क’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत सप्ताह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों को अपने राज्य में करने निवेश करने का न्यौता देने गये। ऐसे में योगी जी उसी दिशा में चल पड़े हैं, जिस पर हरेक मुख्यमंत्री और सरकार को चलना ही चाहिए। कोई भी प्रदेश निजी क्षेत्र के निवेश के बिना चौतरफा विकास कर ही नहीं सकता। आपको देसी-विदेश निवेश तो आर्कर्षित करना ही होगा। इसी क्रम में आपको अपने राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण भी बनाना होगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी खुलकर आए। ये अपने आप में सुखद हैं कि अब अधिकतर राज्य अपने यहां निवेश लाने के लिए तगड़ी पहल कर रहे हैं। इनमें एक तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी है। इसका निश्चित तौर पर स्वागत तो होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो राज्य जितने ठोस कदम उठाएंगे निवेश को खोंचने के लिए, उन्हें उतना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डीआई) और देश के अंदर से ही प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी मिलेगा। यों तो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्रमशः मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और के. चंद्रशेखर राव में एक अद्भुत समानता भी है। ये दोनों अपने-अपने प्रदेश में निवेश लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और, महाराष्ट्र और गुजरात तो परम्परागत रूप से देश के दो इस तरह के राज्य हैं, जहां पर निवेश का वातावरण शुरू से ही रहा है। दरअसल, भारत की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का रास्ता इन दोनों ही राज्यों से होकर गुजरता है। इस बीच, भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) हर साल एक सूची जारी करने लगा है जो यह बताता है कि देश के कौन से राज्य बिजनेस करने के लिहाज से उत्तम हैं। इस पूरी कवायद के पीछे एक मात्र लक्ष्य, राज्यों के बीच निवेश और विकास को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इस सूची में वे ही राज्य आगे निकल रहे हैं, जहां पर औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन की उपलब्धता है, लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कमर्शियल विवाद के लिए ईफाइलिंग की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, वगैरह-वगैरह। लेकिन उत्तर प्रदेशमें उद्यमियों की सबसे बड़ी चिंता राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर है। दुर्भाग्य रहा उत्तर प्रदेश का कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद गुंडागर्दी आम बात हो गई और सरकारी अप्सरों तथा सरकारी पार्टियों के नेताओं द्वारा लूट की राशि बढ़ती ही गई। उत्तम प्रदेश को “उलटा प्रदेश” बनाकर रख दिया विगत दो दशकों के शासकों ने। ऐसा भी नहीं है कि निवेशकों के बजट में “चन्दा” और “सुविधा शुल्क” का प्रावधान नहीं होता। जरूर होता है। लेकिन, दाल में नमक के बराबर! असीमित नहीं। अब कोई दाल से ज्यादा नमक ही मांगने लगे तो क्या अंजाम होगा? एक बात तो समझ ही लेनी चाहिए कि हरेक कारोबारी का लक्ष्य अधिक से अधिक मुनाफा। कमाना ही होता है। अधिक लाभ के लिए भारतीय कंपनियां हीं या विदेशी सभी यही करने लगी हैं। बिहार में सत्तर के दशक में डॉ. जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए पांच औद्योगिक विकास प्राधिकरण बने थे। ये पटना, मुजफ्फरपुर, बोकारो, रांची और आदित्यपुर (जमशेदपुर) में बनाई गई थीं। इनमें से तीन तो झारखण्ड में चली गई। बिहार की दो अर्थोरिटी पटना और मुजफ्फरपुर भी बंद प्राय हो गई हैं। इसलिए निवेशक भी भाग गए। अब पटना औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर कहीं फिल्म निर्माता प्रकाश झा मॉल, होटल और मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं तो कहीं स्कूल खुल रहे हैं तो कहीं गाड़ियों के शो रूम। राज्य सरकार को अब राज्य में निवेश के नए सिरे से उपाय खोजने होंगे।

फोटोग्राफी

न्यूजीलैंड
में रो
फार्म के
नाम से
मशहूर
रकीइंग
रुट का
परफैक्ट
हेलिकाप्टर
शॉट



यह फोटो न्यूजीलैंड में क्रीनस्टाउन और बनाका के बीच है, जिसे स्तो फार्म कहा जाता है। सर्दियों आते ही यहां का पूरा वातावरण सफेद रंग का हो जाता है। इसके बारे में फोटोग्राफर रेट्किलफने लिखा कि उन्होंने ऐसे दृश्य खदानों में देखे थे, लेकिन यह खदान का नहीं बल्कि क्रॉस-कट्री स्काइंग रुट है। वे स्कीअर नहीं थे, लेकिन इस दृश्य को विलक करने के लिए उन्होंने हेलिकॉप्टर की मददली और पूरा स्कीइंग रुट कवर किया। यहां काम करने वाली संस्था ने ऊपर की तरफ कुछ के बिन तैयार किए हैं, जहां मौसम खराब होने जैसी स्थितियों स्कीअर्स कुछ दिन ठहर सकते हैं। जब सर्दियों के बाद बर्फ पिघल जाती है तो यहां पूरे वातावरण में हरियाली छाजाती है। Notey.com

